

हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का राजकोषीय कार्य-निष्पादन

पी. एस. रावत, एट्टेम अभिग्नु यादव,
अत्रि मुखर्जी¹

यह अध्ययन हाल की अवधि में 11 हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की राजकोषीय स्थिति का गहन विश्लेषण करता है। उनके राजकोषीय घाटे में तेजी से वृद्धि हुई है और ऋण वहनीयता संकेतकों की स्थिति बिगड़ रही है। चूंकि इन राज्यों की स्वयं के राजस्व संसाधन जुटाने की क्षमता सीमित है, इसलिए 2015 में उनकी विशेष श्रेणी की स्थिति समाप्त होने के बाद भी उन्हें केंद्र से बड़े हस्तांतरण प्राप्त होते हैं। हालांकि, हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के व्यय की गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों में कुछ सुधार देखा गया है, भले ही उनके ऋण का स्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में लगातार अधिक बना हुआ है।

भूमिका

भारत विविध स्थलाकृति का देश है, जिसमें ऊंचे पहाड़, व्यापक पठार, व्यापक मैदान और लंबी तटरेखा है। स्थलाकृतिक विविधता के परिणामस्वरूप राज्यों में अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुआ है। ग्यारह हिमालयी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश¹ - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर², त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड - अपने पहाड़ी इलाकों के कारण, भौगोलिक अलगाव, अल्प संसाधन आधार और खराब बुनियादी ढांचे³ जैसी विभिन्न नुकसानों से पीड़ित हैं।

¹ लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) से हैं। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को दर्शाते हों।

² नीति आयोग ने 'हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद' का गठन करते समय 'हिमालयी राज्य' शब्द गढ़ा है, जिसमें सभी पूर्ववर्ती विशेष श्रेणी के राज्यों को शामिल किया गया है, जो 15 नवंबर 2018 को वेब लिंक <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1552917> पर अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से है। नीति आयोग की तर्ज पर इस अध्ययन में 'हिमालयी राज्य' शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

³ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, 'जम्मू और कश्मीर' को 31 अक्टूबर 2019 से कानून के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था।

इन बाधाओं के परिणामस्वरूप इन राज्यों में रहने वाले लोगों की गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है (भट्टाचार्य, 2014)। जबकि हिमालयी राज्यों के सामने आने वाली चुनौतियाँ कई हैं, इन राज्यों की लागत अक्षमता और सीमित संसाधन विन्यास के कारण उपलब्ध समाधान कम हैं (बाल्दी, 2014)।

केंद्र सरकार ने उन्हें 'विशेष श्रेणी' का दर्जा देकर और केंद्रीय निधियों तक तरजीही पहुंच के माध्यम से उनके आर्थिक पिछड़ेपन की समस्याओं को हल करने की परिकल्पना करके इस विषयता को दूर करने की कोशिश की। हालांकि, 14वें वित्त आयोग (एफसी-एक्सआईवी) ने 2015 में विशेष श्रेणी के दर्जे की अवधारणा को प्रभावी ढंग से हटा दिया, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इन राज्यों की केंद्रीय सहायता में निरंतरता नहीं रही। इसके बजाय, अंतरराज्यीय असमानताओं को दूर करने के लिए कर हस्तांतरण और अनुदान के माध्यम से राज्यों को संसाधनों का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए।

हाल की अवधि में, दुनिया भर में सरकारी वित्त महामारी, भू-राजनीतिक अनिश्चितता, लगातार उच्च मुद्रास्फीति, समकालिक मौद्रिक नीति कठोरता और वैश्विक विकास मंदी के रूप में कई वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के कारण गंभीर दबाव में आ गया। अप्रैल 2024 में प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2019 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 84.2 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में लगभग 100 प्रतिशत हो गया और 2024 में इसके 93.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। भारत में, सामान्य सरकारी ऋण स्तर 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के 75.2 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 89.3 प्रतिशत हो गया और तब से 2023-24 में घटकर 81.6 प्रतिशत हो गया। भारत में राज्य सरकारों की समेकित देयताएँ मार्च 2021 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 15 वर्ष के उच्च स्तर

³ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। इस अध्ययन में शामिल 2010-11 से 2023-24 की अवधि के लिए लद्दाख के लिए अलग से राजकोषीय डेटा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, लद्दाख को एक अलग संघ राज्य क्षेत्र के रूप में इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है।

31.0 प्रतिशत पर पहुंच गई। हालांकि मार्च 2024 के अंत में राज्यों का ऋण स्तर घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 27.6 प्रतिशत हो गया, लेकिन कुछ राज्यों का ऋण-से-जीएसडीपी⁴ अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक है।

इस पृष्ठभूमि में, यह आलेख इस बात की जांच करता है कि कैसे हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने हाल की अवधि में अपने राजकोषीय प्रदर्शन के गहन विश्लेषण के माध्यम से अपने सीमित संसाधन आधार के साथ महामारी और भू-राजनीतिक दबावों से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला किया। आलेख 5 खंडों में विभाजित है। खंड II भारत में केंद्र-राज्य राजकोषीय हस्तांतरण तंत्र का वर्णन करता है। खंड III हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की राजकोषीय स्थिति से संबंधित शैलीबद्ध तथ्यों को प्रस्तुत करता है। हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राजकोषीय स्थिति सूचकांक खंड IV में है, जबकि निष्कर्ष खंड V में है।

II. केंद्र से राज्यों को राजकोषीय हस्तांतरण

राजकोषीय हस्तांतरण का उद्देश्य ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन को ठीक करना है। केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को हस्तांतरण का उद्देश्य ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन को ठीक करना है। दूसरी ओर, राज्य सरकारों के बीच आवंटन का उद्देश्य क्षैतिज असंतुलन को ठीक करना है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत, प्रत्येक राज्य संघ सूची में सभी केंद्रीय करों के हिस्से का हकदार है। केंद्रीय करों का यह विभाज्य पूल संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर पांच वर्ष में एक बार गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। 15वें वित्त आयोग (एफ़सी-एक्सवी) की सिफारिश के अनुसार, वर्तमान में, केंद्रीय करों का 41 प्रतिशत राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। इस केंद्रीय हस्तांतरण में अलग-अलग राज्यों के हिस्से को एक सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है जो जनसंख्या, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, आय असमानता, भूमि क्षेत्र, कर प्रयास और वन आवरण जैसे विभिन्न कारकों को उचित महत्व देता है।

⁴ जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद को संदर्भित करता है।

केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के अलावा, राज्यों को केंद्र से अनुदान के रूप में भी धन प्राप्त होता है, जिसे योजना और गैर-योजना दोनों उद्देश्यों के लिए वितरित किया जाता है। योजना अनुदानों में राज्यों की अपनी योजना स्कीमों, केन्द्रीय योजना स्कीमों और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अलग-अलग अनुदान होते हैं। गैर-योजना अनुदान अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं और इसमें राज्यों के गैर-योजना राजस्व घाटे को वित्त पोषित करने के लिए सांविधिक अनुदान, प्रशासन के आधुनिकीकरण के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों से राहत शामिल है। इसके अलावा, राज्य केंद्र से भी धन उधार ले सकते हैं (भट्टाचार्य, 2014)।

5वें वित्त आयोग (एफ़सी-वी) ने 1969 में कुछ वंचित राज्यों को तरजीही वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 'विशेष दर्जा श्रेणी' की अवधारणा पेश की, जो उनकी अंतर्निहित विशेषताओं कम संसाधन आधार और विकास के लिये पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाने के कारण है।

विशेष श्रेणी का दर्जा देने के मानदंड थे: (i) पहाड़ी और दुर्गम इलाके; (ii) कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा; (iii) पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के साथ कार्यनीतिक स्थान; (iv) आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन; और (v) राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति। इन मानदंडों के आधार पर, सभी हिमालयी राज्यों को 1969-2001 की अवधि के दौरान समय के साथ विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था (सारणी 1)। इन विशेष श्रेणी राज्यों (एससीएस) ने अन्य राज्यों की तुलना में कुछ अतिरिक्त वित्तीय लाभों का आनंद लिया⁵।

हिमालयी राज्यों को दिया गया विशेष श्रेणी का दर्जा, हालांकि, कोई संवैधानिक समर्थन नहीं था (भारत सरकार, 2010)। एफ़सी-एक्सआईवी ने 2015 में विशेष श्रेणी के दर्जे की अवधारणा को प्रभावी ढंग से हटा दिया, इस आधार पर कि

⁵ अतिरिक्त लाभों में केंद्रीय धन प्राप्त करने में प्राथमिकता शामिल है; राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत; ऋण-स्वैपिंग और ऋण राहत योजनाओं का लाभ; निवेश आकर्षित करने के लिए सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट कर, आयकर और अन्य करों से छूट; और एक वित्तीय वर्ष में किसी भी खर्च न की गई धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने की सुविधा।

सारणी 1: भारत के हिमालयी राज्य

क्रम सं.	राज्य का नाम	एससीएस प्रदान करने का वर्ष	पूर्व स्थिति (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
1	असम	1969	असम
2	जम्मू और कश्मीर	1969	जम्मू और कश्मीर
3	नागालैंड	1969	असम का हिस्सा
4	हिमाचल प्रदेश	1971	केंद्र शासित प्रदेश
5	मेघालय	1972	असम का हिस्सा
6	मणिपुर	1972	केंद्र शासित प्रदेश
7	त्रिपुरा	1972	केंद्र शासित प्रदेश
8	सिक्किम*	1975	रियासत
9	मिजोरम	1987	केंद्र शासित प्रदेश
10	अरुणाचल प्रदेश	1987	केंद्र शासित प्रदेश
11	उत्तराखंड	2001	उत्तर प्रदेश का हिस्सा

* 1975 से पहले, सिक्किम एक रियासत थी। 16 मई, 1975 को, सिक्किम भारत का 22 वां राज्य बन गया और बाद में इसे विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों की वेबसाइटों

अंतरराज्यीय असमानताओं को दूर करने के लिए कर हस्तांतरण और अनुदान के माध्यम से राज्यों को पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जाएंगे। समिति ने 2015 से 2020 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की। यह भी निर्णय लिया गया कि कुछ राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाएगा जिनके लिए अकेले हस्तांतरण अपर्याप्त होगा।

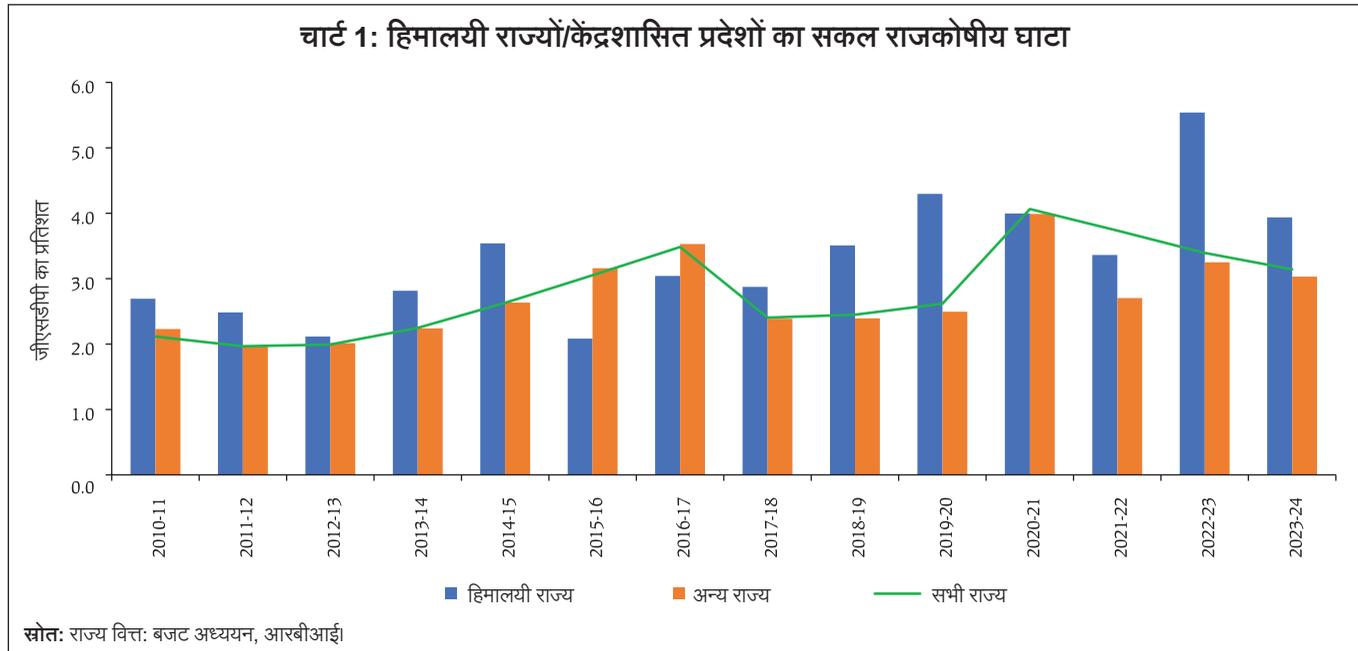
III. शैलीबद्ध तथ्य

III.1 प्रमुख घाटे के संकेतक

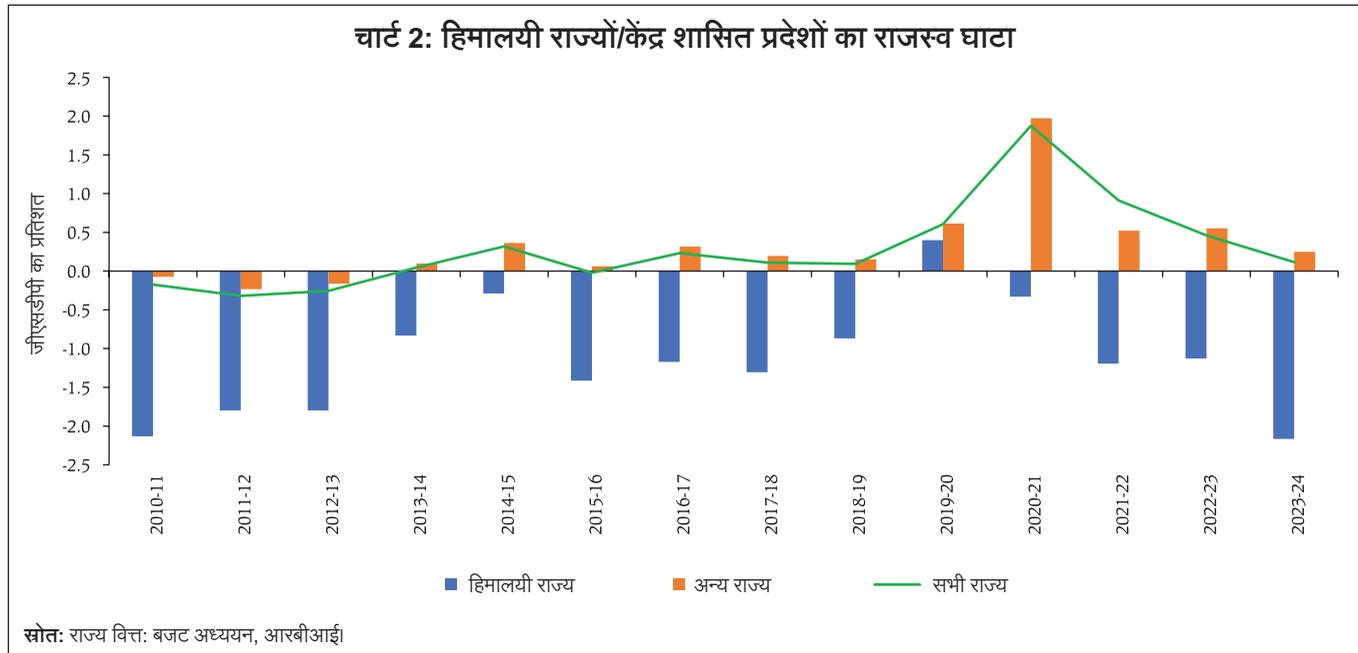
हिमालयी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का समेकित सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2010-11 से 2017-18 की अवधि के दौरान (2014-15 को छोड़कर) जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की एफआरबीएम सीमा के भीतर रहा। हालांकि, उनकी वित्तीय स्थिति बिगड़ गई और जीएफडी 2018-19 के बाद से प्रत्येक वर्ष में 3 प्रतिशत के स्तर को पार कर गया। अधिकांश वर्षों में, हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का जीएफडी 2015-16 और 2016-17 को छोड़कर अन्य राज्यों के समेकित जीएफडी से ऊपर रहा है। जबकि एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद घाटे के प्रबंधन में अधिकांश भारतीय राज्यों के प्रदर्शन में सुधार हुआ, हिमालयी राज्यों के लिये सुधार कम स्पष्ट था (सैकिया, 2022)। हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य राज्यों के जीएफडी के बीच अंतर पिछले पांच वर्षों में काफी बढ़ गया है (चार्ट 1)⁶।

दिलचस्प बात यह है कि हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 2019-20 को छोड़कर अध्ययन के तहत पूरी अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष बनाए रखा। कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में उच्च राजस्व अधिशेष उनकी राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय हस्तांतरणों के बड़े हिस्से को दर्शाता है। इसके विपरीत, अन्य राज्यों ने अधिकांश वर्षों में राजस्व घाटा दर्ज किया (चार्ट 2)।

चार्ट 1: हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का सकल राजकोषीय घाटा



⁶ अध्ययन की अवधि के डेटा में 2021-22 के लिए वास्तविक, 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान और 2023-24 के लिए बजट अनुमान शामिल हैं।

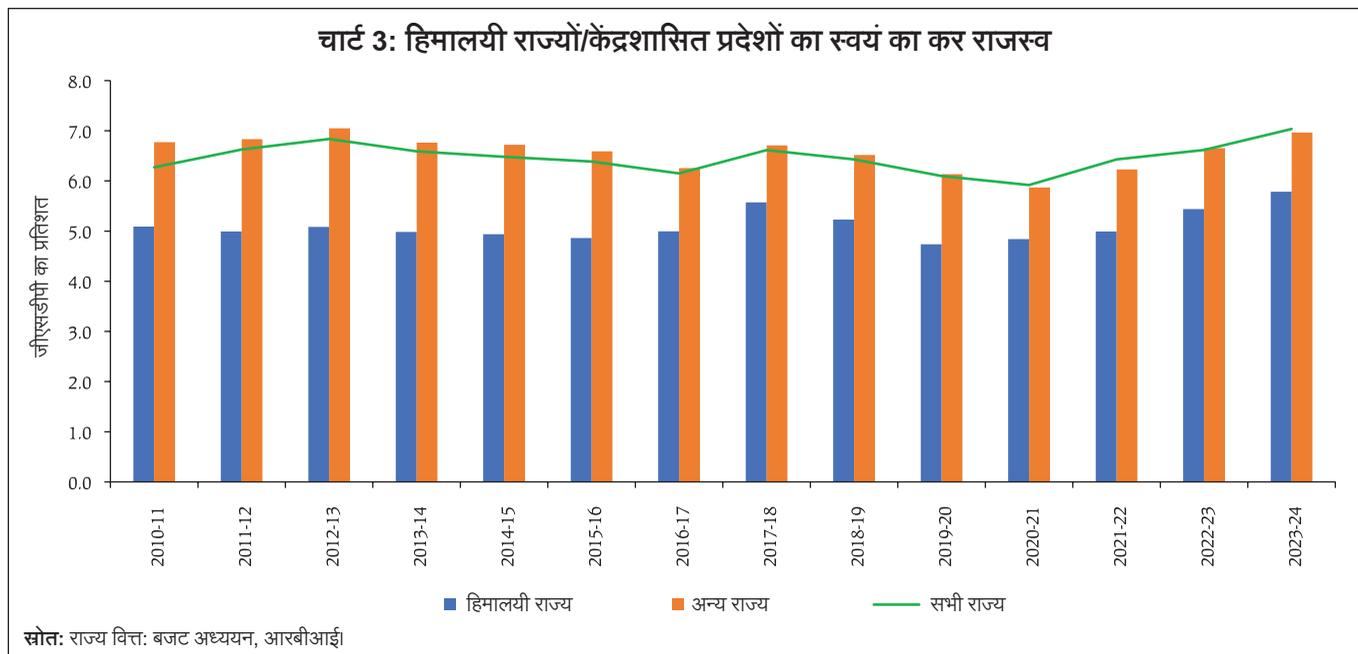


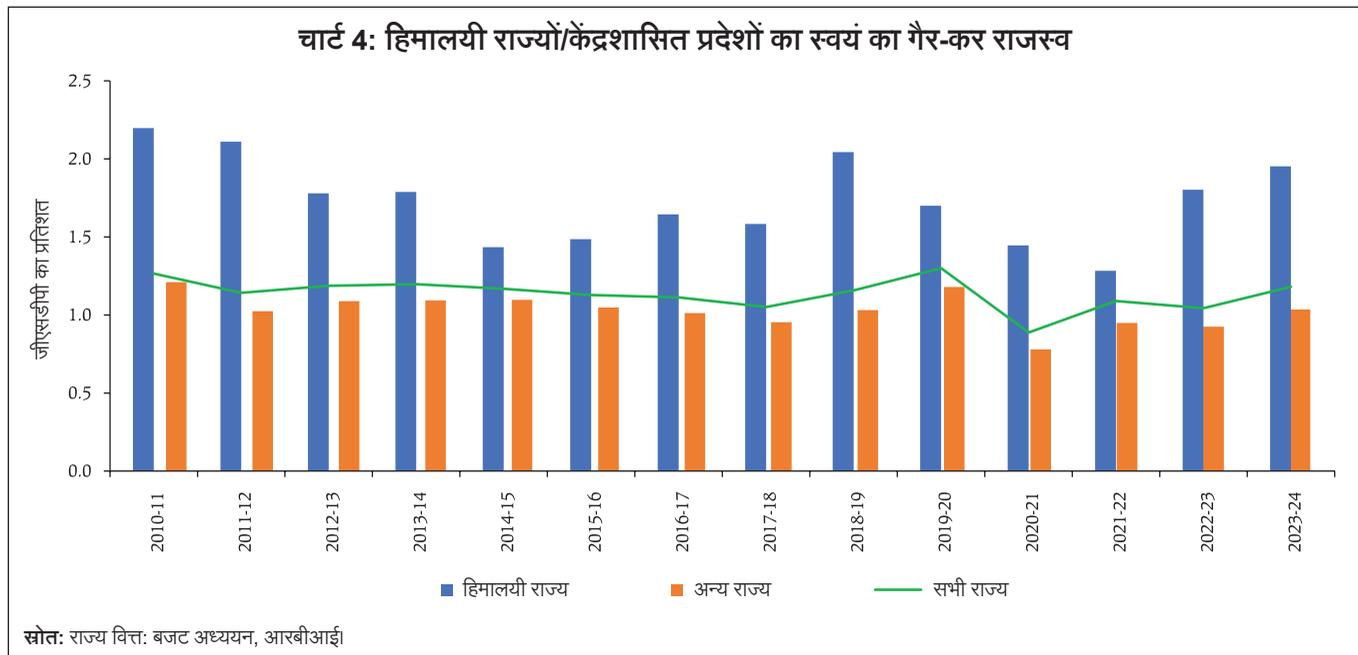
III.2 राजस्व जुटाना

III.2.1 स्वयं का कर राजस्व

भारतीय राज्यों के स्वयं कर राजस्व में आम तौर पर स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क; भूमि राजस्व; पेशेवर कर; संपत्ति कर; बिक्री कर; उत्पाद शुल्क; और राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) से संग्रह शामिल होता है। कम आर्थिक गतिविधि के कारण हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की

अपने कर राजस्व जुटाने की क्षमता सीमित है। हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 1,76,551 रुपये अनुमानित है, जो अखिल भारतीय औसत 1,98,147 रुपये से कम है। हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का स्वयं कर राजस्व आम तौर पर अध्ययन के तहत अधिकांश अवधि (2010-11 से 2023-24) के दौरान जीएसडीपी का लगभग 5 प्रतिशत रहा, जबकि अन्य राज्यों के लिए 6-7 प्रतिशत (चार्ट 3)। उत्तर-पूर्वी राज्य जीएसटी





व्यवस्था के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं, जिन्होंने सभी राज्यों के लिए 14.8 प्रतिशत की तुलना में इसके कार्यान्वयन के बाद से 27.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक जीएसटी राजस्व वृद्धि दर दर्ज की है (आरबीआई 2023)।

III.2.2 स्वयं का गैर-कर राजस्व

अधिकांश भारतीय राज्यों के लिए, गैर-कर राजस्व के मुख्य स्रोतों में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर शुल्क शामिल हैं। हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का गैर-कर राजस्व अध्ययन अवधि के दौरान जीएसडीपी के 1.3-2.2 प्रतिशत की सीमा में मामूली रहा (चार्ट 4)।

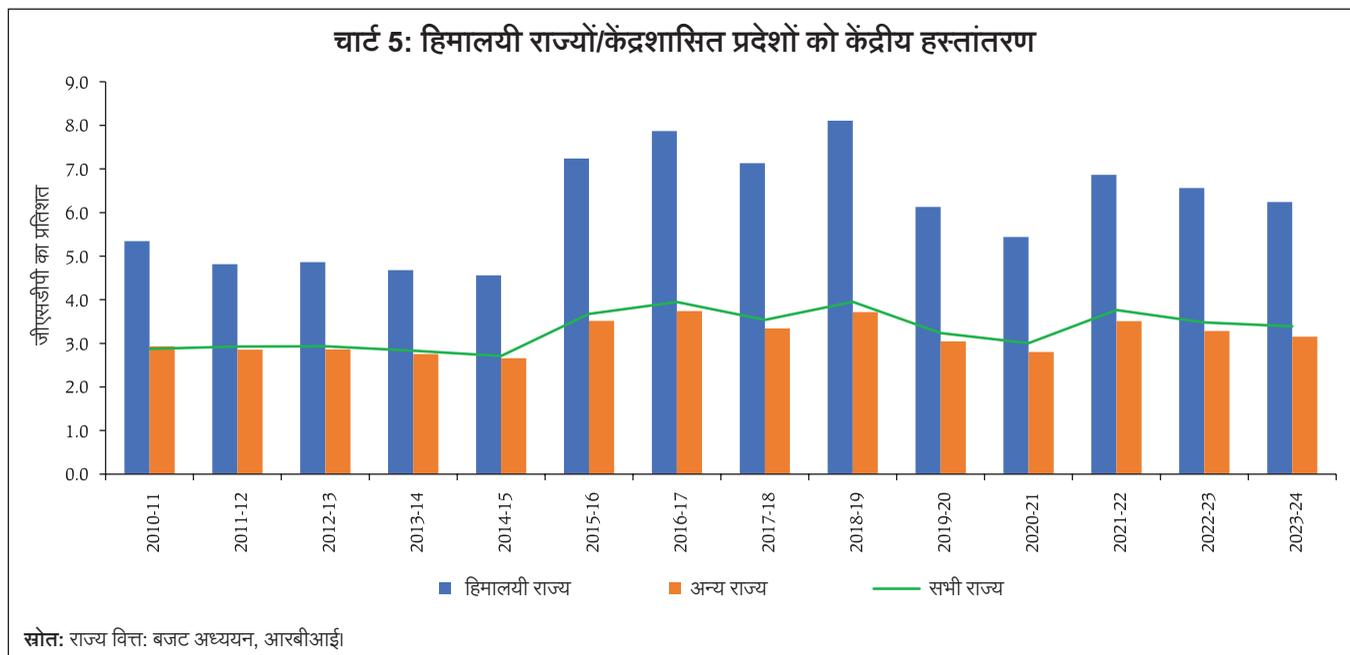
III.2.3 केंद्र से संसाधन हस्तांतरण

राज्यों को केंद्र के वर्तमान हस्तांतरण में कर हस्तांतरण और अनुदान शामिल हैं, जो इस तरह के व्यय के वित्तपोषण के लिए राज्यों की व्यय प्रतिबद्धताओं और अपने स्वयं के संसाधनों के बीच संसाधन अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन के तहत अवधि के दौरान, हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र से अधिक हस्तांतरण प्राप्त हुआ (चार्ट 5)। 14वें वित्त वर्ष द्वारा 2015 में विशेष श्रेणी का दर्जा हटाए जाने के बाद भी इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च हस्तांतरण प्राप्त होते रहे।

राजस्व के लिए केंद्र पर हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की यह भारी निर्भरता उन्हें और असहाय बनाती है। पहला, केंद्र सरकार के राजस्व बंटवारे के पैटर्न में अचानक गिरावट उनके व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। दूसरा, केंद्र द्वारा हस्तांतरित निधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विशिष्ट उद्देश्यों से जुड़ा होता है, जिससे व्यय में राज्यों का लचीलापन सीमित हो जाता है। ये कारक राज्य की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं, और सामाजिक, आर्थिक और सामान्य सेवाओं के वितरण को प्रभावित कर सकते हैं (प्रधान 2023)। तदनुसार, हिमालयी राज्यों को राजस्व के नए स्रोतों की पहचान करके और/या अपने कर प्रशासन को मजबूत करने के साथ-साथ मौजूदा स्रोतों का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठाकर केंद्र से हस्तांतरण के बजाय स्वयं कर राजस्व पर अधिक निर्भर होने से लाभ होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं/उपयोगिताओं के लिए ली जाने वाली मौजूदा दरों को संशोधित करके राज्य अपने गैर-कर राजस्व को भी बढ़ा सकते हैं (प्रधान 2023)।

III.3 व्यय की गुणवत्ता

हिमालयी राज्यों, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में, सार्वजनिक व्यय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि निजी निवेश नगण्य है (सरमा और नायक 2006; नायक और रथ, 2016)। तदनुसार, हिमालयी राज्यों के जीएसडीपी

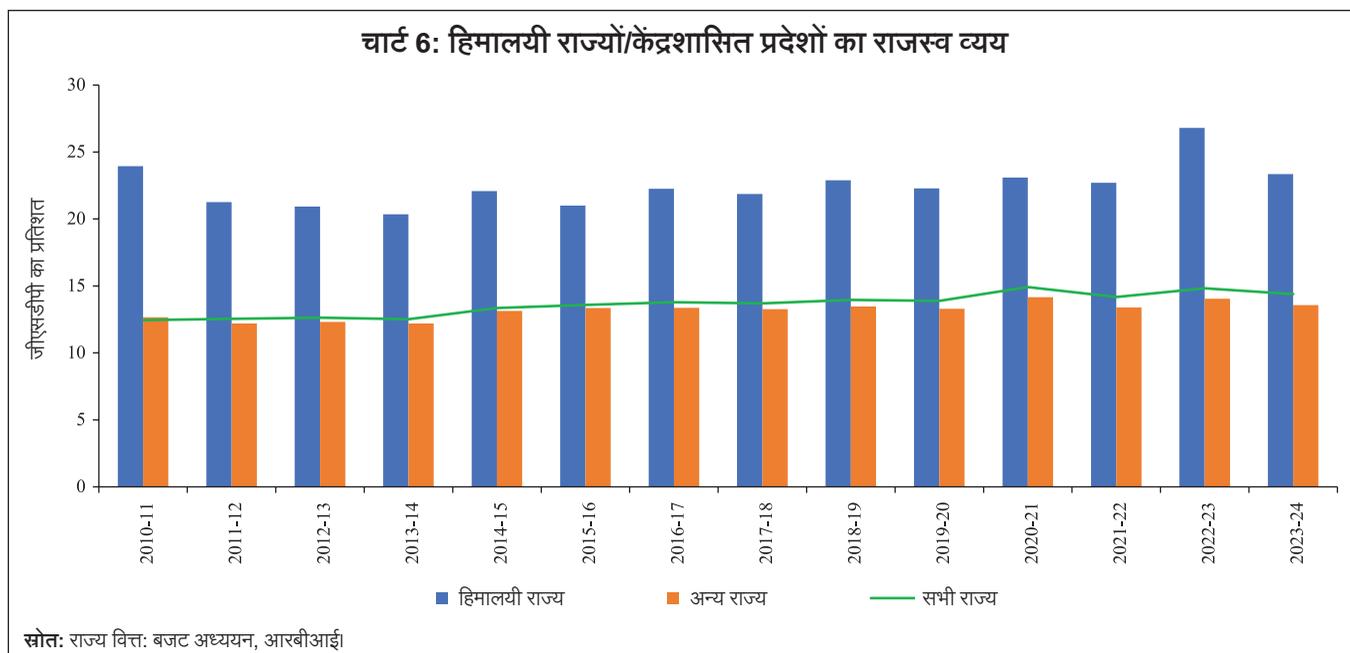


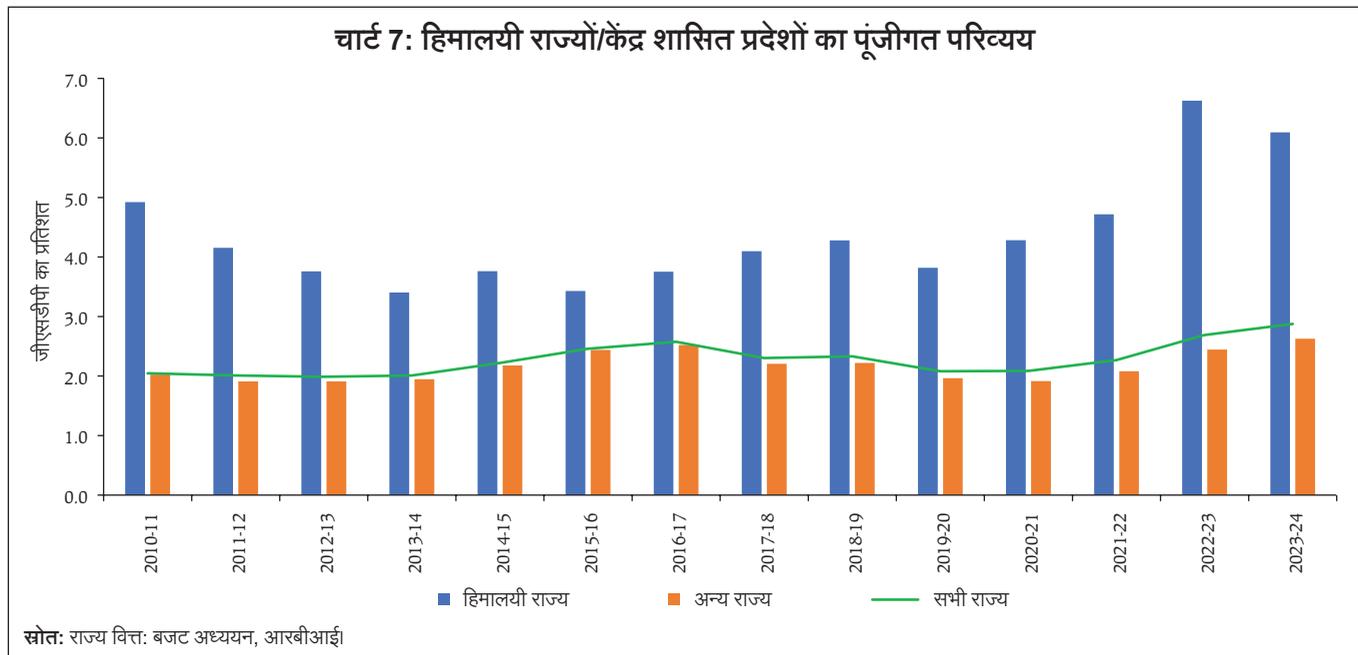
में सार्वजनिक व्यय का हिस्सा अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है।

III.3.1 राजस्व व्यय

हिमालयी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का जीएसडीपी (आरई-जीएसडीपी) और राजस्व व्यय का अनुपात हाल की अवधि में अंतर बढ़ने के साथ अन्य राज्यों की तुलना में लगातार अधिक है (चार्ट 6)। हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की

आरई-जीएसडीपी, जो अध्ययन अवधि के दौरान 20-24 प्रतिशत के दायरे में बढ़ी है, 2022-23 के संशोधित अनुमानों में 26 प्रतिशत को पार कर गई थी। दूसरी ओर, अन्य राज्यों का आरई-जीएसडीपी 12-14 प्रतिशत के दायरे में बना हुआ है। राजस्व व्यय के अधिकांश उप-घटक, अर्थात् ब्याज भुगतान, पेंशन और हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक व्यय अन्य राज्यों की तुलना में अधिक थे।





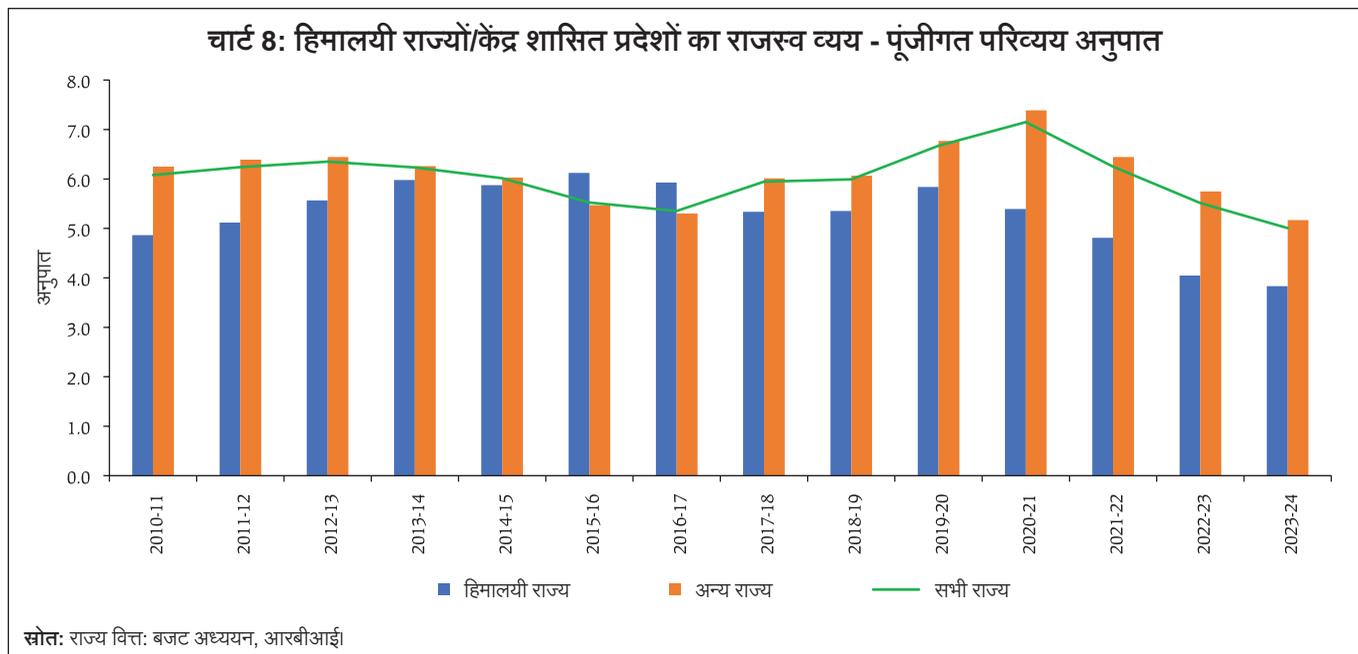
III.3.2 पूंजी परिव्यय

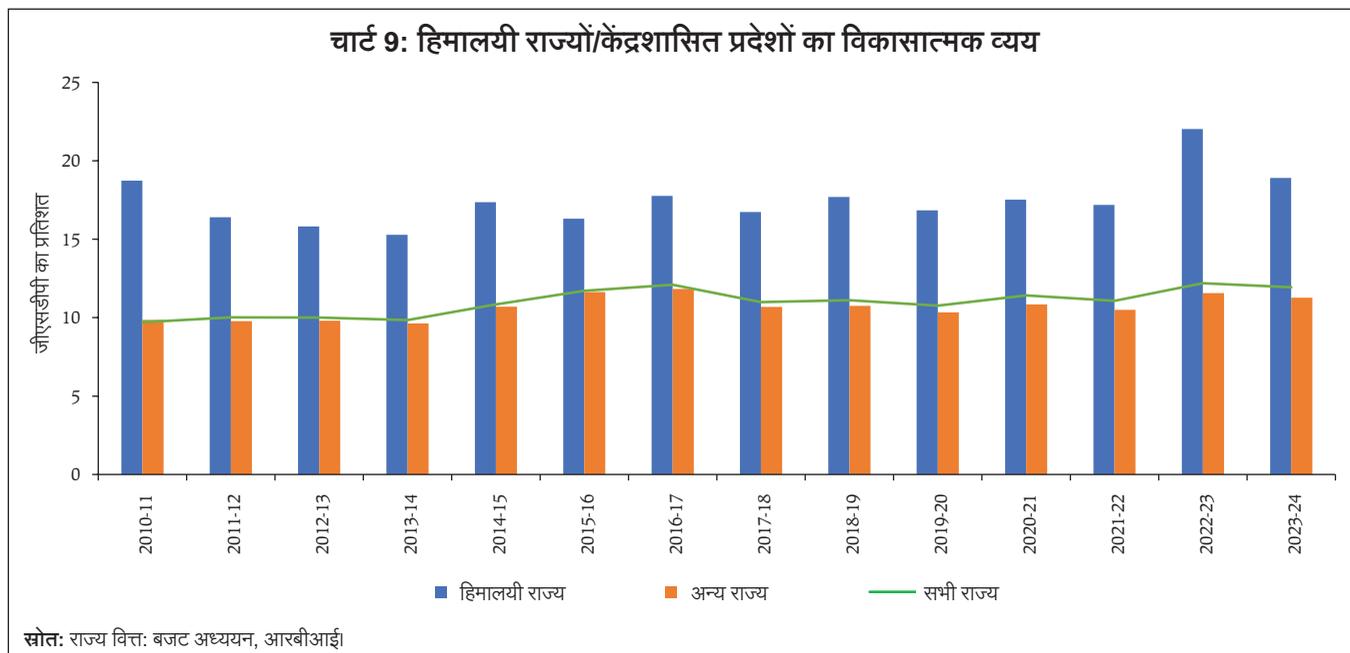
राजस्व व्यय के मामले की तरह, हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का पूंजीगत परिव्यय भी अध्ययन अवधि के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक रहा है। कोविड के बाद की अवधि में हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत परिव्यय में तेजी से वृद्धि हुई, जिसे आंशिक रूप से 2020-21 और 2021-22 के लिए 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए

पूंजीगत व्यय परियोजनाओं पर जोर दिए जाने की वजह से है (चार्ट 7)।

III.3.3 राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय अनुपात

हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) अनुपात - व्यय गुणवत्ता का एक संकेतक - अधिकांश अध्ययन अवधि के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में मामूली रूप से कम था (चार्ट 8)। हिमालयी राज्यों/





केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आरईसीओ अनुपात में 2020-21 के बाद से भारी गिरावट देखी गई, जो महामारी के बाद की अवधि में उनके व्यय की गुणवत्ता में और सुधार का संकेत देता है।

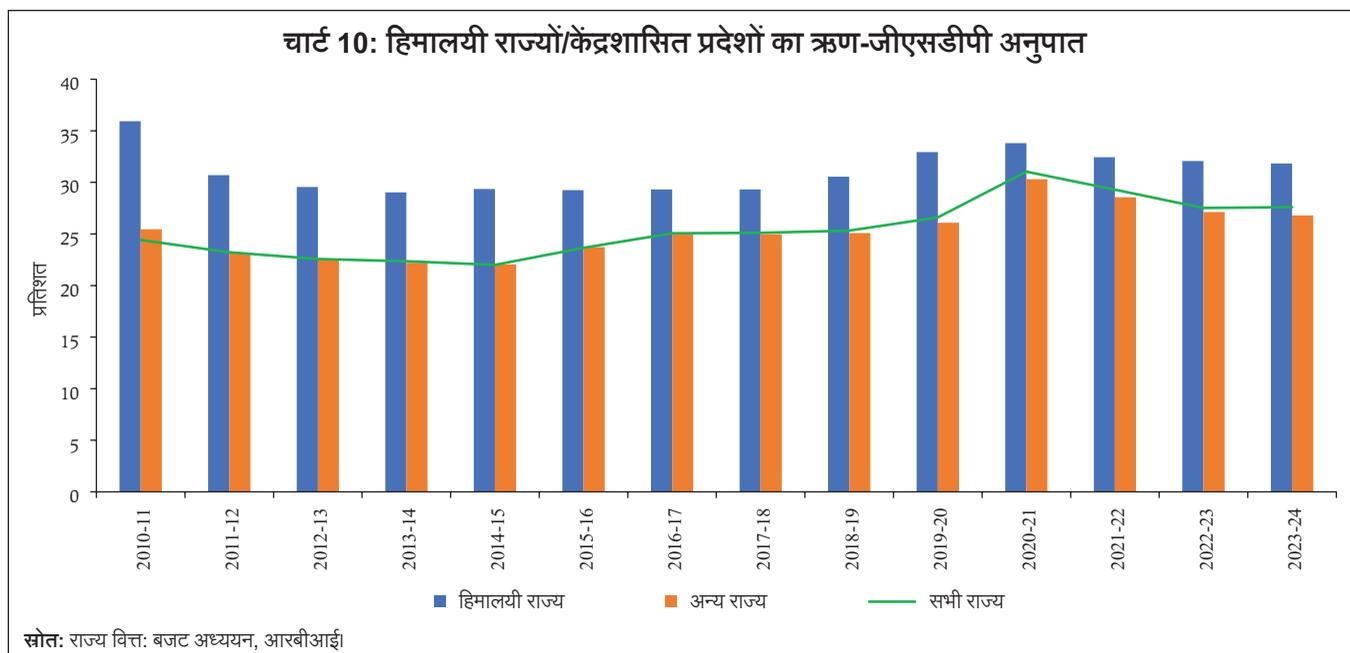
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का विकासात्मक व्यय अध्ययन के तहत अवधि के दौरान जीएसडीपी के 15-22 प्रतिशत की सीमा में ही रहा, जबकि अन्य राज्यों के लिए 9-12 प्रतिशत रहा (चार्ट 9)।

III.3.4 विकासात्मक व्यय

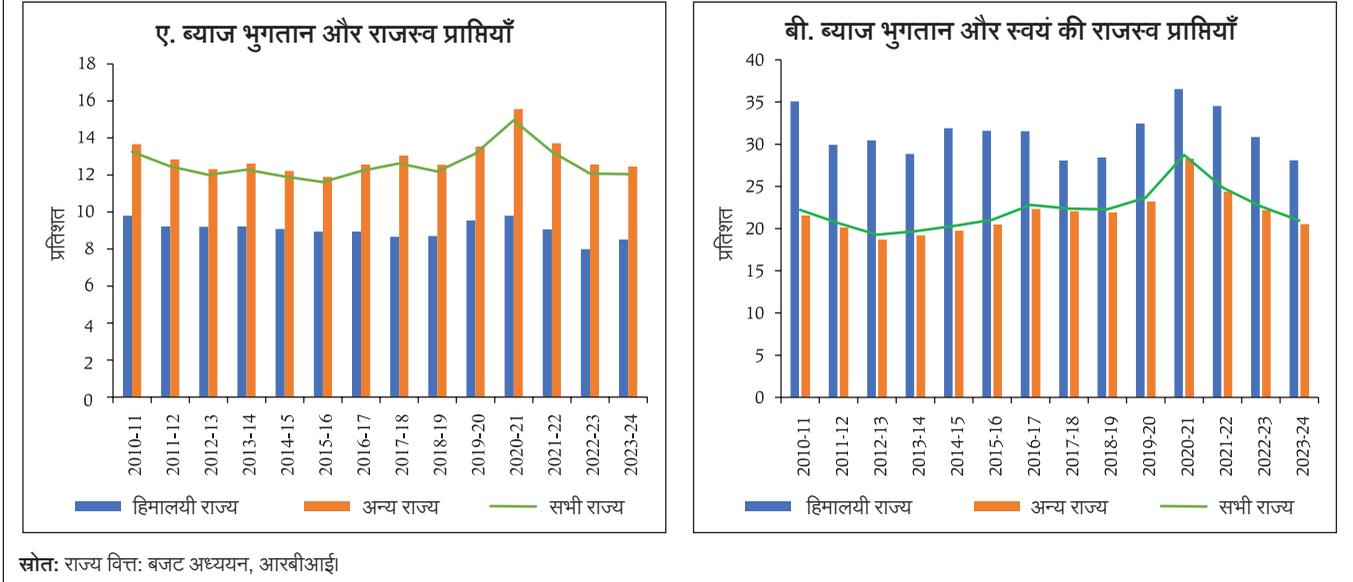
हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का विकासात्मक व्यय अन्य राज्यों की तुलना में उनकी अधिक सामाजिक-आर्थिक विकास आवश्यकताओं के अनुरूप काफी अधिक है। हिमालयी

III.4 ऋण की स्थिति

इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का ऋण-जीएसडीपी अनुपात, जो 2012-13 से 2017-18 की अवधि के दौरान लगभग 29 प्रतिशत था, 2018-19 के बाद से 30 प्रतिशत को



चार्ट 11: हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का ऋण सेवा अनुपात



पार कर गया है (चार्ट 10), जो उच्च राजकोषीय घाटे और कम वृद्धि दर के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। नायक और रथ (2016) ने पाया कि लंबे समय में, असम को छोड़कर किसी भी हिमालयी राज्य में स्थायी ऋण-जीएसडीपी अनुपात नहीं है। ढोलकिया एवं अन्य (2004) ने इन राज्यों के लिए सहनीय ऋण-जीएसडीपी अनुपात प्राप्त करने के लिए प्राथमिक व्यय को कम करने के साथ-साथ उच्च वृद्धि दर की सिफारिश की।

हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ऋण सेवा अनुपात (राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान) अध्ययन के तहत अवधि के दौरान 8.0-9.8 प्रतिशत की सीमा में काफी स्थिर रहा। दूसरी ओर, अन्य राज्यों का ऋण सेवा अनुपात इसी अवधि के दौरान 12-16 प्रतिशत की उच्च सीमा में चला गया (चार्ट 11 ए)। हालांकि, हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान का अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक था, जो कम संसाधन आधार को दर्शाता है (चार्ट 11 बी)।

IV. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक

ढोलकिया और सोलंकी (2001), भिडे और पांडा (2002) और ढोलकिया (2005) के आधार पर कई अध्ययनों ने राजस्व दक्षता, व्यय गुणवत्ता और ऋण स्थिरता जैसे मापदंडों का पता लगाने के लिए भारतीय राज्यों के लिए राजकोषीय प्रदर्शन

सूचकांक विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए, वेंकटरमण (2003) ने छह प्रमुख संकेतकों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजकोषीय घाटा और प्रति व्यक्ति आय शामिल है, जबकि दास और बेग (2014) ने कर्ज के बोझ और राजस्व जुटाने सहित चार महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। मोहंती और मिश्रा (2016) द्वारा प्रस्तावित ढांचे पर विस्तार करते हुए, वर्तमान अध्ययन हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राजकोषीय स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को पांच प्रमुख शीर्षों के तहत व्यवस्थित करता है, अर्थात्, (ए) घाटे के संकेतक, (बी) राजस्व प्रदर्शन संकेतक, (सी) व्यय संकेतकों की गुणवत्ता, (डी) ऋण बोझ संकेतक और (ई) ऋण स्थिरता संकेतक और हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) का निर्माण।

विश्लेषणात्मक सुविधा के लिए, अध्ययन अवधि 2010-11 से 2023-24 को दो उप अवधियों में विभाजित किया गया है: (i) अवधि 1 (2010-11 से 2014-15) – एफसी-एक्सआईवी से पहले की अवधि; और (ii) अवधि 2 (2015-16 से 2023-24) – एफसी-एक्सआईवी के बाद की अवधि (सारणी 2)। इस अवधि का उद्देश्य हिमालयी राज्यों की 'विशेष श्रेणी' की स्थिति को समाप्त करने के एफसी-एक्सआईवी के निर्णय के वित्तीय प्रभाव का निरीक्षण करना है।

सारणी 2: वित्त आयोग और उनकी अवधि	
वित्त आयोग	परिचालन अवधि
13वां	2010-11 से 2014-15
14वां	2015-16 से 2019-20
15वां	2020-21 से 2025-26

स्रोत: भारत सरकार।

IV.1 एफएचआई के घटक

एफएचआई के विभिन्न घटक और उप-घटक इस प्रकार हैं:

(ए) घाटे के संकेतक

- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व घाटा।
- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा।

(बी) राजस्व प्रदर्शन संकेतक

- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में स्वयं का कर राजस्व।
- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में स्वयं का गैर-कर राजस्व।

(सी) व्यय संकेतकों की गुणवत्ता

- राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में विकास राजस्व व्यय।
- राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय का विकास।

(डी) ऋण बोझ संकेतक

- राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान।
- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में ऋण स्टॉक।

(ई) ऋण स्थिरता संकेतक

- जीएसडीपी की वृद्धि दर और ऋण स्टॉक में वृद्धि दर के बीच अंतर के रूप में प्राप्त ऋण प्रसार संकेतक।
- जीएसडीपी की वृद्धि दर और उधार लेने की औसत लागत के बीच अंतर के रूप में प्राप्त दर प्रसार संकेतक। किसी विशेष वर्ष के उधार की औसत लागत प्रभावी ब्याज दर को दर्शाती है,

अर्थात्, पिछले वर्ष के ऋण स्टॉक और चालू वर्ष के ब्याज भुगतान का अनुपात।

IV.2 पद्धति

यह अध्ययन राजकोषीय स्थिति सूचकांक के निर्माण के लिए सापेक्ष दूरी पद्धति का उपयोग करता है। सापेक्ष दूरी पद्धति में अवलोकनों या चरों की तुलना उनके निरपेक्ष मूल्यों के बजाय डेटासेट के भीतर उनकी सापेक्ष स्थिति के संदर्भ में करना शामिल है। यह दृष्टिकोण डेटा बिंदुओं के बीच पैटर्न, समानताएं और अंतर की पहचान करने में मदद करता है। दो डेटा बिंदुओं के बीच की दूरी को पैरामीट्रिक और गैर-पैरामीट्रिक दोनों विधियों के माध्यम से मापा जा सकता है। जबकि पैरामीट्रिक विधियां डेटा के अंतर्निहित वितरण के बारे में विशिष्ट धारणाएं बनाती हैं, गैर-पैरामीट्रिक विधियां उसी के बारे में न्यूनतम धारणाएं बनाती हैं। पैरामीट्रिक विधियां अक्सर कम्प्यूटेशनल रूप से कुशल और व्याख्या करने में आसान होती हैं, लेकिन अंतर्निहित मान्यताओं का उल्लंघन होने पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं। गैर-पैरामीट्रिक विधियों का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब वितरण अज्ञात होता है या किसी विशिष्ट रूप का पालन करने के लिए नहीं माना जा सकता है। गैर-पैरामीट्रिक विधियां डेटा के अंतर्निहित वितरण के लिए मजबूत हैं, लेकिन खासकर बड़े डेटासेट के लिए कम्प्यूटेशनल रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। इस प्रकार, पैरामीट्रिक और गैर-पैरामीट्रिक दोनों विधियों के अपने फायदे और नुकसान हैं, और उनके बीच का चुनाव अक्सर डेटा की प्रकृति और उस समय की विशिष्ट समस्या पर निर्भर करता है। यह अध्ययन राजकोषीय स्थिति सूचकांक⁷ के निर्माण के लिए डेटा बिंदुओं को स्केल करने या सामान्य करने की न्यूनतम-अधिकतम (गैर-पैरामीट्रिक) विधि के साथ सापेक्ष दूरी का उपयोग करता है।

⁷ सापेक्ष दूरी पद्धति, चाहे पैरामीट्रिक या गैर-पैरामीट्रिक को विभिन्न पूर्वाग्रहों के अधीन किया जा सकता है जो उनके परिणामों की सटीकता और वैधता को प्रभावित करते हैं। सापेक्ष दूरी में ऊपर की ओर पूर्वाग्रह, डेटा बिंदुओं के बीच की गणना की गई दूरी को लगातार कम करके आंकने या बढ़ाने की एक व्यवस्थित प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यह पूर्वाग्रह इस धारणा को मिटा सकता है कि अंक एक-दूसरे से कितने भिन्न या दूर हैं, संभावित रूप से गलत विश्लेषण या निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। सापेक्ष दूरी में ऊपर की ओर पूर्वाग्रह को संबोधित करने के लिए बूटस्ट्रैपिंग तकनीक में बूटस्ट्रैप रीसैप्लिंग, कंप्यूटिंग सापेक्ष दूरी, पूर्वाग्रह सुधार, आत्मविश्वास अंतराल, सत्यापन और संवेदनशीलता विश्लेषण शामिल हैं। बूटस्ट्रैपिंग का दायरा, हालांकि, इस अध्ययन में संभव नहीं है क्योंकि रीसैप्लिंग में सीमा है।

पहले चरण में, ऊपर वर्णित प्रत्येक संकेतक का स्तर 0 से 100 तक के सूचकांक मान के लिए सामान्यीकृत होता है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (पीक्यूएलआई) (मॉरिस, 1982) और मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति के समान है। यह विधि एक सूचकांक बनाने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों मापदंडों को ले सकती है। अनुकूल संकेतकों के लिए बनाए गए सूचकांक को सुधार सूचकांक कहा जाता है। प्रतिकूल मापदंडों को लेकर बनने वाले सूचकांक को अभाव सूचकांक कहा जाता है। दोनों सूचकांकों का मान 0 और 100 के बीच होगा।

$$\text{अभाव सूचकांक (डी)} = \frac{[\text{अधिकतम (एक्स)} - \text{एक्स}] * 100}{[\text{अधिकतम (एक्स)} - \text{न्यूनतम (एक्स)}}$$

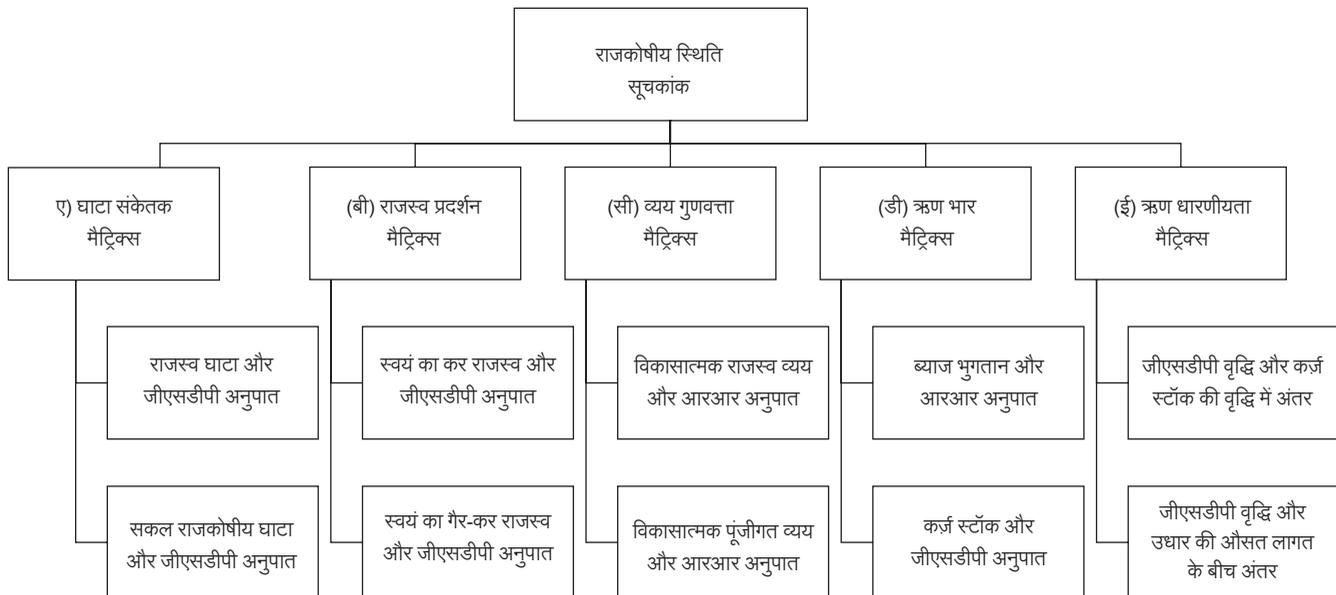
$$\text{सुधार सूचकांक} = \frac{[\text{एक्स} - \text{न्यूनतम (एक्स)}] * 100}{[\text{अधिकतम (एक्स)} - \text{न्यूनतम (एक्स)}}$$

जहां, एक्स किसी दिए गए राज्य के लिए पैरामीटर के वास्तविक मान को संदर्भित करता है। अधिकतम (एक्स) और न्यूनतम (एक्स) एक निर्दिष्ट अवधि में राज्यों में पैरामीटर का

अधिकतम और न्यूनतम मान हैं। डी और आई का मान 0 से 100 के पैमाने पर होगा जहां 0 सबसे खराब प्रदर्शन को दर्शाता है और 100 का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।

इस अध्ययन में, सामान्यीकरण के लिए, अभाव सूचकांक के फार्मूले को घाटे के संकेतकों और ऋण बोझ संकेतकों पर लागू किया जाता है क्योंकि वे राज्य के राजकोषीय स्थिति से नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होते हैं। दूसरी ओर, सुधार सूचकांक के लिए सूत्र राजस्व प्रदर्शन संकेतकों, व्यय संकेतकों की गुणवत्ता और ऋण स्थिरता संकेतकों पर लागू किया जाता है क्योंकि वे राजकोषीय प्रदर्शन से सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होते हैं। अगले चरण में, पांच अलग-अलग शीर्षों में से प्रत्येक के तहत सामान्यीकृत संकेतकों के औसत की गणना पांच अलग-अलग मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए की जाती है: घाटा संकेतक मैट्रिक्स, राजस्व प्रदर्शन मैट्रिक्स, व्यय गुणवत्ता मैट्रिक्स, ऋण बोझ मैट्रिक्स और ऋण वहनीयता मैट्रिक्स। इन पांच मैट्रिक्स का साधारण औसत समग्र राजकोषीय स्थिति सूचकांक (एफएचआई) प्रदान करता है (सारणी 3)।

सारणी 3: राजकोषीय स्थिति सूचकांक की संरचना



स्रोत: लेखकों की व्याख्या।

IV.3 परिणाम

एफएचआई से हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राजकोषीय स्थिति में बड़े उतार-चढ़ाव का पता चलता है (सारणी 4)। अवधि -1 में, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शीर्ष चार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हिमालयी राज्यों के रूप में उभरे। इस अवधि के दौरान हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का एफएचआई मान त्रिपुरा के लिए 55 से जम्मू और कश्मीर के लिए 40 तक था। दूसरी ओर, अवधि -2 में, मिजोरम, असम और त्रिपुरा हिमालयी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के बीच शीर्ष तीन स्थानों पर रहे। मेघालय, जो अवधि 1 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक था, अवधि 2 में 8 वें स्थान पर खिसक गया। अधिकांश हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एफएचआई मान में अवधि 2 में गिरावट आई, जो उनके राजकोषीय स्थिति पर दबाव को दर्शाता है (चार्ट 12)। मेघालय (14 अंक) के मामले में यह सबसे तेज गिरावट है, इसके बाद उत्तराखंड (12 अंक) और त्रिपुरा (7 अंक) का स्थान है। एकमात्र अपवाद असम है जिसने एफएचआई मान में 2 अंकों का सुधार देखा है। दिलचस्प बात यह है कि अन्य राज्यों के एफएचआई में भी अवधि 1 और अवधि 2 के बीच गिरावट आई, मुख्य रूप से कम कर राजस्व, उच्च व्यय और घाटे के संकेतकों में परिणामी वृद्धि के संदर्भ में राज्य वित्त पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण (चार्ट 12)। तथापि,

अन्य राज्यों के एफएचआई मान हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक बने रहे।

अधिकांश हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, अवधि 2 में घाटे के संकेतक मैट्रिक्स में गिरावट आई है (परिशिष्ट सारणी ए); इसका श्रेय कोविड-19 महामारी को दिया जा सकता है, जिसने भारतीय राज्यों के समेकित जीएफडी को 2020-21 में जीडीपी के 4.1 प्रतिशत के शिखर पर पहुंचा दिया।

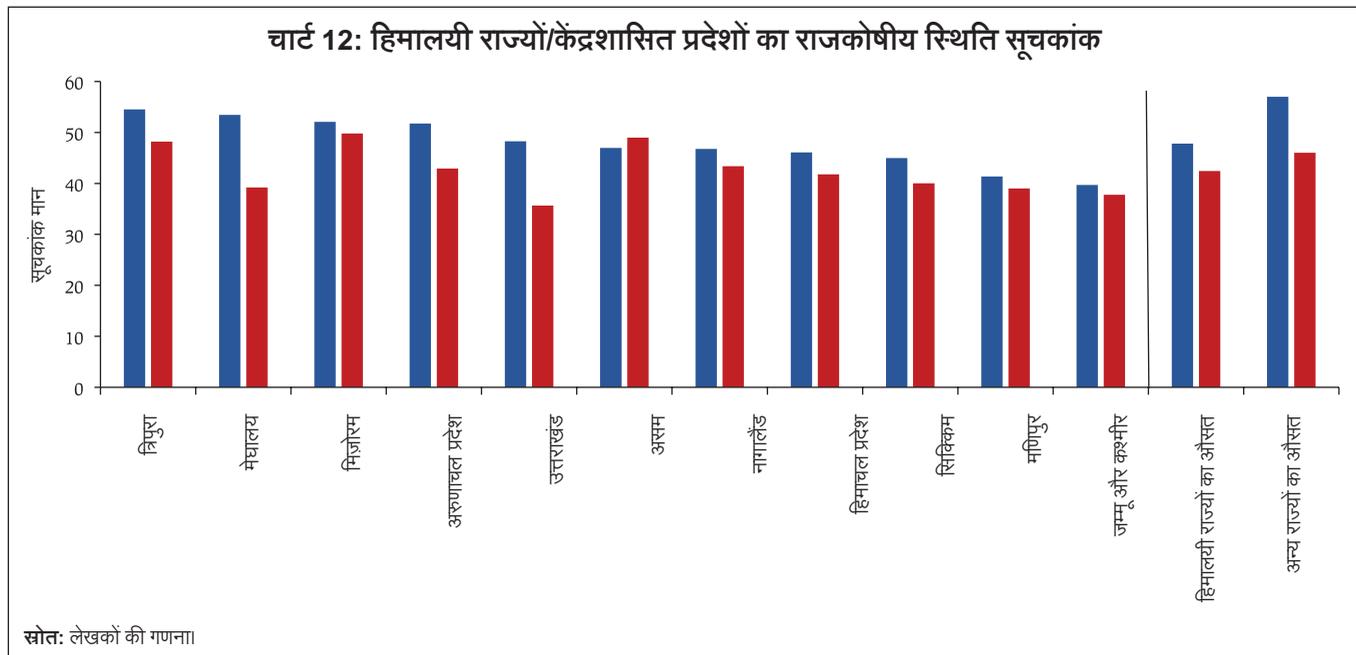
राजस्व प्रदर्शन मैट्रिक्स के संदर्भ में हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से बेहतर था क्योंकि छह राज्यों ने अवधि 2 (परिशिष्ट सारणी बी) में अपने स्कोर में सुधार किया था। मेघालय का अवधि 2 में सबसे अच्छा राजस्व प्रदर्शन था, इसके बाद उत्तराखंड और मिजोरम थे। व्यय मैट्रिक्स की गुणवत्ता के संदर्भ में, पांच राज्यों ने व्यय की गुणवत्ता में सुधार दिखाया और छह राज्यों ने अवधि 2 में गिरावट दिखाई (परिशिष्ट सारणी सी)।

हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का ऋण बोझ मैट्रिक्स एक मिश्रित तस्वीर दिखाता है, जिनमें से छह ने अवधि 1 की तुलना में अवधि 2 में उच्च स्कोर दर्ज किया (परिशिष्ट सारणी डी)। दूसरी ओर, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और सिक्किम जैसे राज्यों के लिए मैट्रिक्स मूल्य 30 से कम के साथ सभी हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का ऋण स्थिरता मैट्रिक्स अवधि 2 में कम हो गया (परिशिष्ट सारणी ई)।

सारणी 4: हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एफएचआई मान

अवधि 1 (2010-11 से 2014-15)			अवधि 2 (2015-16 से 2023-24)		
श्रेणी	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 1	श्रेणी	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 2
1	त्रिपुरा	55	1	मिजोरम	50
2	मेघालय	53	2	असम	49
3	मिजोरम	52	3	त्रिपुरा	48
4	अरुणाचल प्रदेश	52	4	नागालैंड	43
5	उत्तराखंड	48	5	अरुणाचल प्रदेश	43
6	असम	47	6	हिमाचल प्रदेश	42
7	नागालैंड	47	7	सिक्किम	40
8	हिमाचल प्रदेश	46	8	मेघालय	39
9	सिक्किम	45	9	मणिपुर	39
10	मणिपुर	41	10	जम्मू और कश्मीर	38
11	जम्मू और कश्मीर	40	11	उत्तराखंड	36

स्रोत: लेखकों की गणना



V. निष्कर्ष

हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की समग्र राजकोषीय स्थिति ने पिछले पाँच वर्षों में दबाव प्रदर्शित किया, उनके समेकित जीएफडी ने 2019-20, 2020-21 और 2022-23 में जीएसडीपी के 4 प्रतिशत का उल्लंघन किया। इस अवधि के दौरान हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य राज्यों के जीएफडी के बीच अंतर बढ़ गया है। हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की स्वयं कर राजस्व जुटाने की क्षमता उनकी आर्थिक और भौगोलिक संरचना से उत्पन्न चुनौतियों के कारण बाधित रहती है। हिमालयी राज्यों के आर्थिक विकास में सार्वजनिक व्यय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इन राज्यों में निजी निवेश सीमित है। तदनुसार, इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जीएसडीपी में सार्वजनिक व्यय का हिस्सा भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। आरईसीओ अनुपात के संदर्भ में मापे गए हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के व्यय की गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से सुधार हुआ है।

हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का ऋण स्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में लगातार अधिक रहा है। अलग-अलग स्तर पर, हिमालयी राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन में

बड़े अंतर-राज्यीय अंतर हैं और इनमें से अधिकांश राज्यों के राजकोषीय स्थिति सूचकांक मान में हाल की अवधि में गिरावट आई है। राजकोषीय निष्पादन के विभिन्न संकेतकों में से घाटे और ऋण वहनीयता संकेतकों ने राजकोषीय स्थिति को देखते हुए राजकोषीय समेकन की बढ़ती मांग में सर्वाधिक योगदान दिया है। हिमालयी राज्यों का 2015 में उनकी विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त होने के बाद भी केंद्र से उच्च हस्तांतरण प्राप्त करना जारी है। इससे खर्च में उनका लचीलापन कम हो सकता है और इसलिए इन राज्यों को राजस्व के नए स्रोतों की पहचान करने, मौजूदा स्रोतों का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठाने और उच्च संसाधन जुटाने के लिए अपने कर प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

Baldi, S. (2014). Policy issues in revenue generation and expenditure management in hill states with special reference to Himachal Pradesh. *Journal of Governance & Public Policy*, 4(1), 57.

Bhattacharjee, G. (2014). The Reality of Special Category Status. *Economic and Political Weekly*, 49(40), October 4, 2014.

- Bhide, S., & Panda, M. (2002). Evaluating Quality of Budgets with a Composite Index. *Economic and Political Weekly*, March 30.
- Bose, S., Noopur, A., Sri Hari Nayudu. (2022). Intergovernmental Fiscal transfers and Expenditure on Education in India: State level analysis, 2005 to 2020. No. 377, March 2022, *National Institute of Public Finance and Policy*, New Delhi.
- Das, & Baig. (2014). India's State Finances: Declining Debt but Weak Fundamentals. *Deutsche Bank Research*, January 30.
- Dholakia, A., & Solanki, T. (2001). Ranking States on Fiscal Performance. Paper presented at seminar on Economic Reforms, Gujarat University, Ahmedabad, March.
- Dholakia, A. (2005). Measuring Fiscal Performance of States: An Alternative Approach. *Economic and Political Weekly*, July 30.
- GoI (2010), Available at: <https://sansad.in/getFile/annex/221/Au2559.pdf?source=pqars>
- Mohanty, A. R., & Mishra, B. R. (2016). Fiscal Performance Index of the States in India. *NIBM*, Pune.
- Nayak, S. K., and Rath, S. S. (2016). A Study on Debt Problem of the Special Category States. Study Conducted for the 13th Finance Commission, Government of India.
- Pradhan (2013). <https://www.thehindu.com/data/data-the-risk-of-small-states-heavy-reliance-on-the-union-government/article67095283.ece>
- RBI 2023, State Finances: A Study of Budgets of 2022-23, Reserve Bank of India, January 2023.
- Saikia, B., Roy, C. S., & Shah, S. (2022). FRBM Act and fiscal performance of the special category states of India: A trend analysis. *Social Change and Development*, 1-17.
- Sarma, A., & Nayak, S. K. (2006). Growth and Equity in the Post-Reform Period: Experience of the North Eastern States. Paper presented at the Silver Jubilee Conference of the CESS, Hyderabad, January 7th-8th.
- The Gazette of India, Ministry of Home Affairs. (2019, August 09). NOTIFICATION (Department of Jammu and Kashmir Affairs). *New Delhi*.
- Venkatraman, K. (2003). Towards a Fiscal Responsibility Index: Some Preliminary Analysis. *Vishleshan*, 28(4), October-December.

परिशिष्ट सारणियाँ

ए. घाटा सूचकांक मैट्रिक्स

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 1	अवधि 2	परिवर्तन
1	अरुणाचल प्रदेश	49	59	10
2	असम	64	55	-9
3	हिमाचल प्रदेश	60	66	6
4	जम्मू और कश्मीर	49	46	-3
5	मणिपुर	52	38	-14
6	मेघालय	59	53	-6
7	मिजोरम	27	58	31
8	नागालैंड	69	48	-21
9	सिक्किम	77	48	-30
10	त्रिपुरा	81	31	-49
11	उत्तराखंड	61	38	-23

स्रोत: लेखकों की गणना।

बी. राजस्व प्रदर्शन मैट्रिक्स

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 1	अवधि 2	परिवर्तन
1	अरुणाचल प्रदेश	23	31	8
2	असम	58	41	-17
3	हिमाचल प्रदेश	58	29	-29
4	जम्मू और कश्मीर	27	42	16
5	मणिपुर	36	31	-6
6	मेघालय	39	51	11
7	मिजोरम	29	46	18
8	नागालैंड	24	43	19
9	सिक्किम	58	29	-29
10	त्रिपुरा	60	26	-33
11	उत्तराखंड	19	47	28

स्रोत: लेखकों की गणना।

सी. व्यय मैट्रिक्स की गुणवत्ता

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 1	अवधि 2	परिवर्तन
1	अरुणाचल प्रदेश	54	39	-15
2	असम	24	54	30
3	हिमाचल प्रदेश	25	30	5
4	जम्मू और कश्मीर	43	42	-1
5	मणिपुर	38	51	13
6	मेघालय	58	50	-8
7	मिजोरम	66	44	-22
8	नागालैंड	50	42	-8
9	सिक्किम	20	49	29
10	त्रिपुरा	34	49	16
11	उत्तराखंड	54	34	-19

स्रोत: लेखकों की गणना।

डी. कर्ज भार मैट्रिक्स

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 1	अवधि 2	परिवर्तन
1	अरुणाचल प्रदेश	60	70	10
2	असम	63	58	-4
3	हिमाचल प्रदेश	43	65	21
4	जम्मू और कश्मीर	43	57	14
5	मणिपुर	37	69	32
6	मेघालय	83	44	-40
7	मिजोरम	25	80	54
8	नागालैंड	31	62	31
9	सिक्किम	80	49	-31
10	त्रिपुरा	63	61	-2
11	उत्तराखंड	73	44	-29

स्रोत: लेखकों की गणना।

ई. कर्ज धारणीयता मैट्रिक्स

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 1	अवधि 2	परिवर्तन
1	अरुणाचल प्रदेश	79	47	-33
2	असम	65	41	-23
3	हिमाचल प्रदेश	62	34	-27
4	जम्मू और कश्मीर	37	24	-13
5	मणिपुर	42	24	-18
6	मेघालय	52	37	-15
7	मिजोरम	72	56	-16
8	नागालैंड	41	34	-8
9	सिक्किम	48	25	-24
10	त्रिपुरा	65	60	-5
11	उत्तराखंड	54	24	-29

स्रोत: लेखकों की गणना।

